HRA Sazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102]

नई दिल्ली, श्क्रवार, अप्रैल 15, 2005/चैत्र 25, 1927

No. 102]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 15, 2005/CHAITRA 25, 1927

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2005

'8.07 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2017' की बिक्री (युनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(2)-डक्ल्यू एंड एम/2005.— भारत सरकार एतदद्वारा 5,000 करोड़ रुपए(नामिनल) की कुल राशि के लिए '8.07 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक, 2017' की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ संख्या 4(9)-डब्ल्यूएण्डएम/2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

निर्गम की विधि

2. सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से दिनांक 6 मई,2002 की सामान्य अधिसूचना एफ. संख्या 4(9)-डब्ल्यूएंडएम/2000 के पैरा 5.1 में निर्धारित तरीके से एक समान मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

 सरकारी प्रतिभृतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 19 अप्रैल, 2005 को संचालित की जाएगी। बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 19 अप्रैल, 2005 को अपराह्न 12.30 बजे तक उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

अवधि

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भूगतान

- 6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट, मुंबई कार्यालय में 19 अप्रैल, 2005 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 20 अप्रैल, 2005 अर्थात पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टाक के नामिनल मूल्य पर स्टॉक की अविध प्रारम्भ होने की तारीख अर्थात 15 जनवरी, 2005 से 19 अप्रैल, 2005 तक उपचित ब्याज शामिल होगा।
- 7. स्टॉक की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से स्टॉक के नामिनल मूल्य पर प्रतिवर्ष 8.07 प्रतिशत की दर से ब्याज उपचित होगा तथा इसका भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर 15 जुलाई तथा 15 जनवरी को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से एल. एम. वास, संयुक्त सचिव अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

I. कार्यक्षेत्र: सरकारी प्रतिभृतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभृतियों की चयनित नीलामियों में 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभृतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।

II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलागियों में अप्रविस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदार्श खुली होगी जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं :

1.जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं ; अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत रखते हुए इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।

- 2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनिधक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं ;
- 3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद: ऐसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता: उपर्युक्त शर्तों के अधीन 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर फर्मों, कंपनियों, निगमित निकायों, संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश:

1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथिमक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथिमक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।

- 2. निश्चित आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलार कीलायी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करेगा। अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा ग्रधा- नाम, राशि आदि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाम/कीमत की उस भाराशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलाभी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने प्राप्तकों से मुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बैंक या प्राथमिक डालर को प्रतिभृतिया जारी की जाएंगी।
- 4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसृचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक है यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह वैंक अथवा प्राशिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभृतियों का उचित आवंटन एक गारदर्शी तरोंके से करें।
- 5. ऐसे मामले में जहां बोली रांशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कसी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा।
- 5. प्रतिभृति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसाकि उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक टीलरों को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मृत्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तविक रूप में की गई सुपूर्वगी रहीकार्य है।
- 7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित कर। असाधारण परिस्थितियां को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्धम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- 8. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए प्रति सो रुपए छह पैसे तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीभत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहा प्रतिभृतियों का अंतरण प्रतिभृति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपचित ब्याज शामिल होगा।
- 9. प्रतिभृतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली,बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।
- V. बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) के योजनांतर्गत संचालनों से संबंधित सूचना जो बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समय-समय पर मंगाई जाए,प्रस्तुत करनी होगी।
- VI. जपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योर्जना को संशोधित किया जाएगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BUDGET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2005

Auction for Sale (Re-issue) of '8.07 per cent Government Stock, 2017'

F.No. 4(2)-W&M/2005.—Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '8.07 per cent Government Stock, 2017' for an aggregate amount of Rs. 5,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F.No. 4 (9)-W&M/2000 dated May 6, 2002 issued by Government of India as amended from time to time.

Method of Issue

2. The Government Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4(9)-W&M/2000 dated May 6, 2002 by a price based auction using uniform price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annexure).

Place and date of auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on April 19, 2005. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on April 19, 2005 by 12.30 P.M.

Teaure

5. The Stock will be of fifteen year tenure commencing from January 15, 2002. The Stock will be repaid at par on January 15, 2017.

Date of issue and payment for the Stock

6. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai office on April 19, 2005. The payment by successful bidders will be on April 20, 2005, i.e., the date of reissue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the last coupon payment date, i.e., January 15, 2005 to April 19, 2005.

Interest

7. Interest at the rate of 8.07 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of commencement of the tenure and will be paid half yearly on July 15 and January 15.

ANNEXURE

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. <u>Scope</u>: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

II. <u>Eligibility</u>: Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:

1. do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

- 2. make a *single* bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.
- 3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. <u>Coverage</u>: Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines:

- 1. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.
- 2. Each bank or PD on the basis of *firm* orders submit a single *customer bid* for the aggregate amount on the day of the auction. Details of individual customers' viz. name, amount, etc. shall be provided as an Annexure to the bid.

1231 527 2005-2

- 3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.
- 4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
- 5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.
- 6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.
- 7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.
- 8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.
- 9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.
- V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.
- VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.

अधिस्चना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2005

'7.50 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034' की विक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

फा. सं. 4(2) - इस्ट्यू एंड एम/2005 (i).— भारत सरकार एतदद्वारा 2,000 करोड़ रुपए(नामिनल) की कुल राशि के लिए '7.50 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक, 2034' की बिक्री (पुनर्निर्गम) अधिसूचित करती है। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ संख्या 4(9)-डब्ल्यूएण्डएम/2000 दिनांक 6 मई, 2002 में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन की जाएगी।

निर्गम की विधि

2. सरकारी स्टॉक की बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 के माध्यम से दिनाक 6 मई,2002 की सामान्य अधिसूचना एफ. संख्या 4(9)-डब्ल्यूएंडएम/2000 के पैरा 5.1 में निर्धारित तरीके से अनेक मूल्य नीलामी विधि का प्रयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी द्वारा की जाएगी।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

3. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

4. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा 19 अप्रैल, 2005 को संचालित की जाएगी। बोलियों सहित विधिवत भरे गए आवेदन-पत्र 19 अप्रैल, 2005 को अपराह्न 12.30 बजे तक उपर्युक्त कार्यालय में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए।

अवधि

5. स्टॉक तीस वर्ष की अवधि के लिए होगा जो 10 अगस्त, 2004 से प्रारंभ होगी। स्टॉक की वापसी-अदायगी 10 अगस्त, 2034 को सममूल्य पर की जाएगी।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए मुगतान

- 6. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट, मुंबई कार्यालय में 19 अप्रैल, 2005 को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 20 अप्रैल, 2005 अर्थात पुनर्निर्गम की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टाक के नामिनल मूल्य पर स्टॉक की अवधि प्रारम्भ होने की तारीख अर्थात् 10 फरवरी, 2005 से 19 अप्रैल, 2005 तक उपचित ब्याज शामिल होगा।
- 7. स्टॉक की अवधि के प्रारम्भ होने की तारीख से स्टॉक के नामिनल मूल्य पर प्रतिवर्ष 7.50 प्रतिशत की दर से ब्याज उपचित होगा तथा इसका भुगतान अर्ध-वार्षिक आधार पर 10 अगस्त तथा 10 फरवरी को किया जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से एल. एम. वास, संयुक्त सचिव

अनुबंध

सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा स्कीम

- I. कार्यक्षेत्र: सरकारी प्रतिभूतियों की व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की चयनित नीलामियों में 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर भागीदारी की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। तदनुसार, दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की अप्रतिस्पर्धी बोलियां स्वीकार की जाएंगी। प्रारक्षित राशि अधिसूचित राशि के अन्तर्गत होगी।
- II. पात्रता : भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी आधार पर ऐसे निवेशकों के लिए भागीदारी खुली होगी जो निम्नलिखित शतों को पूरा करते हैं :
 - 1.जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास चालू खाता (सीए) अथवा सहायक सामान्य बही (एसजीएल) खाता नहीं रखते हैं ; अपवाद : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों को उनके सांविधिक दायित्वों के दृष्टिगत रखते हुए इस स्कीम के अधीन शामिल किया जाएगा।
 - 2. जो प्रति नीलामी दो करोड़ रुपए (अंकित मूल्य) से अनधिक राशि के लिए एक ही बोली लगाते हैं ;
 - 3. जो यह स्कीम प्रदान करने वाले किसी एक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के माध्यम से अपनी बोली अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

अपवाद : ऐसे दोत्रीय प्रामीण बैंक (आरआरबी) तथा सहकारी बैंक जो भारतीय रिजर्व वैंक में एस.जी.एल.खाता और चालू खाता रखते हैं, अपनी अप्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे।

III. व्यापकता : उपर्युक्त शर्तों के अधीन 'अप्रतिस्पर्धी' आधार पर फर्मी, कंपनियों, निगमित निकायों,संस्थाओं, भविष्य निधियों, न्यासों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित किसी अन्य कंपनी सहित किसी भी व्यक्ति के लिए भागीदारी खुली है। बोली देने की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए (अंकित मूल्य) और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में होगी जैसा अब तक दिनांकित स्टॉक के लिए है।

IV. अन्य प्रचालनात्मक दिशानिर्देश:

- 1. खुदरा निवेशक के लिए उस बैंक अथवा प्राथमिक डीलर, जिनके माध्यम से वे भाग लेना चाहते हैं, के पास एक संघटक सहायक सामान्य बही (सीएसजीएल) खाता रखना अनिवार्य नहीं होगा। तथापि, कोई भी निवेशक इस स्कीम के अधीन केवल एक बोली दे सकता है। इस आशय का वचन कि निवेशक केवल एक बोली दे रहा है, बैंक अथवा प्राथमिक डीलर द्वारा प्राप्त किया जाना और रिकार्ड में रखा जाना आवश्यक होगा।
- 2. निश्चित आदेश के आधार पर प्रत्येक बैंक अथवा प्राथमिक डीलर नीलामी के दिन कुल राशि के लिए एकल ग्राहक बोली प्रस्तुत करेगा। अलग-अलग ग्राहकों का ब्यौरा यथा- नाम, राशि आदि बोली के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 3. बैंक अथवा प्राथमिक डीलर को अप्रतिस्पर्धी खंड के अधीन आबंटन प्रतिलाभ/कीमत की उस भारांशित औसत दर पर होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली देने के आधार पर नीलामी में सामने आएगी। इस बात पर ध्यान दिए बिना कि बैंक अथवा प्राथमिक डीलर ने अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त कर लिया है या नहीं, निर्गम की तारीख को भुगतान प्राप्त करके बेंक या प्राथमिक डालर को प्रतिभृतियां जारी की जाएंगी।

4. ऐसे मामले में, जहां बोली की राशि प्रारक्षित राशि (अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत) से अधिक हैं यथानुपात आबंटन किया जाएगा। आंशिक आबंटनों के मामले में, यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलरों का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने ग्राहकों को प्रतिभृतियों का उचित आबंटन एक पारदर्शी तरीके से करे।

- 5. ऐसे मामले में जहां बोली राशि प्रारक्षित राशि से कम हो, कमी को प्रतिस्पर्धी भाग में लिया जाएगा।
- 6. प्रतिभूति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केवल एसजीएल रूप में जारी किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक इसे या तो बैंक अथवा प्राथमिक डीलर के मुख्य एसजीएल खाते अथवा सीएसजीएल खाते में जमा करेगा, जैसािक उनके द्वारा निर्देश दिया गया है। मुख्य एसजीएल खाते में जमा करने की सुविधा एकमात्र उन निवेशकों की सेवा के प्रयोजनार्थ है जो उनके घटक नहीं हैं। अतः बैंक अथवा प्राथमिक डीलरो को अप्रतिस्पर्धी बोलियों की निविदा देते समय उनके एसजीएल खाते और सीएसजीएल खाते में जमा होने वाली राशियों (अंकित मूल्य) को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। बाद में निवेशक के अनुरोध पर मुख्य एसजीएल खाते से वास्तिविक रूप में की गई सुपूर्दगी रवीकार्य है।
- 7. यह बैंक अथवा प्राथमिक डीलर का उत्तरदायित्व है कि वह ग्राहक को प्रतिभूतियां हस्तांतिरत कर। असाधारण परिस्थितियां को छोड़कर, ग्राहकों को प्रतिभूतियों का अंतरण निर्गम की तिथि से पांच कार्य दिवसों के भीतर पूरा किया जाएगा।
- 8 बैंक अथवा प्राथमिक डीलर अपने ग्राहकों को यह सेवा देने के लिए प्रति सां रुपए छह पैसे तक दलाली/कमीशन/सेवा प्रभार के रूप में वसूल कर सकते हैं। ऐसी कीमत बिक्री मूल्य में शामिल की जा सकती है। ऐसे मामले में जहां प्रतिभूतियों का अंतरण प्रतिभूति की निर्गम तिथि के बाद प्रभावी होता हो, बैंक या प्राथमिक डीलर को ग्राहक द्वारा देय प्रतिफल राशि में निर्गम तिथि से उपिवत ब्याज शामिल होगा।
- 9. प्रतिभृतियों की लागत, उपचित ब्याज जहां भी लागू हो, तथा दलाली/कमीशन/सेवा प्रभारों के लिए ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने की कार्य-प्रणाली,बैंक या प्राथमिक डीलर द्वारा ग्राहक के साथ की गई सहमति के अनुसार तैयार की जाएगी। यह उल्लेखनीय है कि कोई अन्य लागत, जैसे निधिकरण लागत को मूल्य में शामिल नहीं किया जाना चाहिए या ग्राहकों से वसूल नहीं किया जाना चाहिए।
- V. बैंकों तथा प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिजर्व बैंक (बैंक) के योजनांतर्गत संचालनों से संबंधित सूचना जो बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समय-समय पर मंगाई जाए, प्रस्तुत करनी होगी।
- VI. ऊपर उल्लिखित दिशानिर्देश बैंक द्वारा समीक्षा के अधीन है और तदनुसार, जब भी आवश्यकता होगी, योजना को संशोधित किया जाएगा।

1231 8172005-3

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2005

Auction for Sale (Re-issue) of '7.50 per cent Government Stock, 2034'

F. No. 4(2)-W & M/2005 (i).— Government of India hereby notifies sale (re-issue) of '7.50 per cent Government Stock, 2034' for an aggregate amount of Rs. 2,000 crore (nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called 'Specific Notification') as also the terms and conditions specified in the General Notification F.No. 4 (9)-W&M/2000 dated May 6, 2002 issued by Government of India as amended from time to time.

Method of Issue

2. The Government Stock will be sold through Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 in the manner as prescribed in paragraph 5.1 of the General Notification F. No. 4(9)-W&M/2000 dated May 6, 2002 by a price based auction using multiple price auction method.

Allotment to Non-competitive Bidders

3. Government Stock up to 5% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions as per the enclosed Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities (Annexure).

Place and date of auction

4. The auction will be conducted by Reserve Bank of India, Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on April 19, 2005. The application form duly filled in with the bids should be submitted to the aforesaid office on April 19, 2005 by 12.30 P.M.

Tenure

5. The Stock will be of thirty year tenure commencing from August 10, 2004. The Stock will be repaid at par on August 10, 2034.

Date of issue and payment for the Stock

6. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India at its Fort, Mumbai office on April 19, 2005. The payment by successful bidders will be on April 20, 2005, i.e., the date of reissue. The payment for the Stock will include accrued interest on the nominal value of the Stock allotted in the auction from the last coupon payment date, i.e., February 10, 2005 to April 19, 2005.

Interest

7. Interest at the rate of 7.50 per cent per annum will accrue on the nominal value of the Stock from the date of commencement of the tenure and will be paid half yearly on August 10 and February 10.

ANNEXURE

Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of Government Securities

I. <u>Scope</u>: With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities it is proposed to allow participation on "non-competitive" basis in select auctions of dated Government of India securities. Accordingly, non-competitive bids up to 5 per cent of the notified amount will be accepted in the auctions of dated securities. The reserved amount will be within the notified amount.

II. <u>Eligibility</u>: Participation on a non-competitive basis in the auctions of dated GOI Securities will be open to investors who satisfy the following:

1. do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks shall be covered under this Scheme in view of their statutory obligations.

- 2. make a *single* bid for an amount not more than Rs. two crore (face value) per auction.
- 3. submit their bid *indirectly* through any *one* bank or PD offering this scheme.

Exceptions: Regional Rural Banks (RRBs) and Co-operative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

III. <u>Coverage</u>: Subject to the conditions mentioned above, participation on "non-competitive" basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts, and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples in Rs. 10,000 as hitherto for dated stocks.

IV. Other Operational Guidelines:

- 1. It will *not* be mandatory for the retail investor to maintain a constituent subsidiary general ledger (CSGL) account with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make only a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that the investor is making only a single bid will have to be obtained and kept on record by the bank or PD.
- 2. Each bank or PD on the basis of *firm* orders submit a single *customer bid* for the aggregate amount on the day of the auction. Details of individual customers' viz. name, amount, etc. shall be provided as an Annexure to the bid.
- 3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.

- 4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (5% of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
- 5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion.
- 6. Security would be issued *only* in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the non-competitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account is permissible at the instance of the investor subsequently.
- 7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within *five* working days from the date of issue.
- 8. The bank or PD can recover upto six paise per Rs100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. Such costs may be built into the sale price or recovered separately from the clients. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.
- 9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.
- V. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.
- VI. The aforesaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified.
